newspapers that she could not say anything in support of it. Pension must be given, but after due verification.

**An Adult girl forced to kill herself In Ahmedabad**

**श्रीमती सरला माहेश्वरी** (पश्चिम बंगाल) : सभापति जी, मेरा यह विशेष उल्लेख हाल ही में अहमदाबाद में भारती बारोट नाम की लड़की को प्रेम विवाह करने के जुर्म में जल कर मरने के लिए मजबूर किए जाने की अमानवीय घटना के संबंध में है।

सभापति जी, अभी चार दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के अलीनगर में एक प्रेमी युगल को सिर्फ प्रेम करने के जुर्म में समाज के तथाकथित ठेकेदारों द्वारा सरे आम फांसी लगाए जामे के न्रशंस कांड का मैंने जिक्र किया था । उसकी स्याही सूखी भी नही थी कि अहमदाबाद में इस बार धर्म के ठेकेदारों ने एक नवयुवती के शुद्धिकरण के नाम पर उसे जल कर मर जाने के लिए मजबूर कर दिया ।

भारती बारोट नाम की उस लड़की ने जाति, धर्म ,संप्रदाय के बजाय प्रेम करने के मनुष्य के अधिकार को समझा था और उसने एक मुस्लिम लड़के के साथ अपनी मर्जी से शादी की थी। वह वयस्क थी। लड़का भी वयस्क था। भारत के कानून के अनुसार उन्हें विवाह करने से कोई रोक नहीं सकता था। उन्होंने कानून और मानवीयता के मापदंड पर कोई जुर्म नहीं किया था। उनकी शादी को भले ही मां-बाप की स्वीकृति न मिली हो लेकिन वयस्क होने के नाते वे इस मामले में पूरी तरह स्वतंत्र थे और बाकयदा अदालत में जाकर अपने विवाह का पंजीकरण कराया था। इसके बावजूद अहमदाबाद की पुलिस ने पता नहीं कानून की किस धारा के आधार पर इस वयस्क जोड़े के पंजीकृत विवाह के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली और इस नवविवाहित युगल के खिलाफ ऐसा अभियान शुरु किया कि उन्हें आत्म-समपर्ण करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

पता नहीं कानून की किस धारा के आधार पर लड़की को रिमांड होम में भेज दिया गया और तो और रिमांड होम में भेजी गई वह लड़की किस प्रकार मायावी ठंग से एक तथाकथित धार्मिक संस्था के चंगुल में पहूंचा दि गई जहां बौठे धर्म के ठेकेदारों ने लड़की के शुद्धिकरण का काम शुरु किया।ये शुद्धीकरण ऐसा था कि उस धार्मिक संस्था के दफ्तर में ही लड़की ने आत्महत्या कर ली ।

किसी के भी दिमाग में यह सवाल आएगा कि आखिर थाने-कचहरियां, अदालतें भारत के कानून की रक्षा के लिए बनी हैं या धर्म जाति के नाम पर अपराध करने वालों को संरक्षण देने के लिए? और अब वहां पुलिस ने दुर्घटना के कारण मौत का केस बनाया है। इस हत्याकांड को दुर्घटना का नाम देकर ढकने की पुलिस की कोशिश क्या एक शर्मनाक नहीं है?

मैं इस सदन से निवेदन करना चाहूंगी कि इस जधन्य हत्याकांड के लिए जिम्मेदार संस्था के विरुद्ध मामला दर्ज किया जाए और तमाम सम्बद्ध पक्षों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए ताकि

ऐसे मानवद्रोहियों को उचित सजा मिल सके। गृह मंत्री जी, जिस घटना की पूरी जानकारी लेकर सदन को बयान दें। आप यहां मौजूद हैं। मैं आपसे निवेदन करुंगी कि इस घटना के बारे में, जो कि बहुत ही अमानवीय और बर्बर घटना है और लगातार ऐसी घटनाएं घटती जा रही हैं, तो कम से कम इस सदन के सामने आप घटना की पूरी जानकारी दें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI VIJAY SINGH YADAV (Bihar): Sir, I associate myself with this.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, I also associate myself with this.

SHRI S.G. INDIRA (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with this.

SHRI RAJU PARMAR (Gujarat) : Sir, I too associate myself with this.

**Revival of Internal Security problems**

SHRI SATISH PRADHAN (Maharashtra): Sir, our country has entered this new millennium with a promising future, but we still need to improve a lot to tackle our toughest problems in internal security. Today we are facing problems like infiltration, foreign spy activities and so on. It Is time that we took tough measures. Recently, I read a newsletter of the Department of Atomic Energy published in September/October, 2000. They have mentioned a system by which this problem can be tackled and they have suggested three ways of controlling these activities. The first way is issuing of citizen cards like the phonetic identification system based on alpha/numeric codes. The second method is based on finger print analysis called the anthropological coding system.

The third is based on routine activities of citizens called Watch Dog Index system. These systems were approved by fhe Ministry of Home Affairs in 1986. They tested phonetic identification system and it was successful. But till date, they have not implemented it. These systems can benefit our nation in controlling infiltration, checking foreign spies, precise realistic planning, economic and efficient administration, speedy investigation of crime, aiding security in war-time, reading cost of electoral rolls, quick assessment of measures taken in natural calamities, speedy justice at less cost, implementation of welfare schemes, eliminating duplicated works,